

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS
(DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)

RAJYA SABHA
UNSTARRED QUESTION NO.602
(ANSWERED ON 24.07.2025)

UNFILLED VACANCIES IN MINISTRIES AND DEPARTMENTS

602. SHRI SANJAY RAUT:

Will the **PRIME MINISTER** be pleased to state:

- (a) the total number of sanctioned posts across all Ministries and Departments under Central Government as of March 2021 and how many remain unfilled;
- (b) the number of vacancies in key Ministries such as Railways, Defence, Home Affairs, and the Postal Department;
- (c) whether it is a fact that more than 9.79 lakh posts are lying vacant across 78 Central Ministries and Departments;
- (d) whether such large-scale vacancies contradict Government's commitment to provide 2 crore jobs annually; and
- (e) the specific measures being taken to fill these posts in a time-bound, transparent, and accountable manner to address rising unemployment in the country?

ANSWER

**MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES
AND PENSIONS AND MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER'S OFFICE
(DR. JITENDRA SINGH)**

(a) to (e): The total number of sanctioned posts across all Ministries and Departments under Central Government as on 01.03.2021 was 40,35,203. The occurrence and filling up of vacancies is a continuous process, depending upon the position and requirement in various Ministries / Departments of Central Government. The details of unfilled vacancies and appointments made are maintained by the respective Ministries / Departments. Further, the Pay Research Unit of the Department of Expenditure publishes Annual Reports containing consolidated data relating to sanctioned posts and persons-in-position in various Ministries / Departments. The Annual Reports of the Pay Research Unit are publicly accessible on the website of the Department of Expenditure at: <https://doe.gov.in/hi/annual-report-pay-and-allowances>

The Government has issued instructions to all Ministries / Departments for taking timely and advance action to fill up vacant / unfilled posts through direct recruitment. In terms of these instructions, Ministries / Departments are required to take advance action for reporting their vacancy position in respect of direct recruitment posts to the concerned recruiting agencies in order to facilitate the filling up of direct recruitment vacancies in a timely manner. For filling of vacancies through promotion, a Model Calendar for holding Departmental Promotion Committee (DPC)

meetings has been prescribed. All Ministries/ Departments have been requested to adhere to the prescribed timelines so as to ensure that panels are ready in time and utilised as and when vacancies arise during the course of the vacancy year. For filling of vacant posts through deputation, power has been delegated to Ministries / Departments for making appointments to posts up to level 13A and below in the pay matrix. All these measures have significantly helped in accelerating the pace and quantum of appointments and filling up of vacant posts in Central Government.

Further, since June 2022, vacant posts in Central Government are being filled by the respective Ministries / Departments in mission-mode under Mission Recruitment. Rozgar Melas are being organized in 45-50 cities at regular intervals, which act as a catalyst for the time-bound filling up of vacancies across Central Government Ministries / Departments / Organizations.

भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 602
(24.07.2025 को उत्तर के लिए)

मंत्रालयों और विभागों में रिक्त पद

602. श्री संजय राउत:

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) मार्च 2021 तक केंद्र सरकार के अंतर्गत सभी मंत्रालयों और विभागों में संस्वीकृत पदों की कुल संख्या कितनी है और कितने पद रिक्त हैं;
- (ख) रेल, रक्षा, गृह जैसे प्रमुख मंत्रालयों और डाक विभाग में रिक्त पदों की संख्या कितनी है;
- (ग) क्या यह सच है कि 78 केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों में 9.79 लाख से अधिक पद रिक्त हैं;
- (घ) क्या इतने बड़े पैमाने पर रिक्तियां सरकार की वर्ष में 2 करोड़ नौकरियां प्रदान करने की प्रतिबद्धता के विपरीत हैं: और
- (ङ) देश में बढ़ती बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिए इन पदों को समयबद्ध, पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से भरने के लिए क्या विशिष्ट उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह)

(क) से (ङ): दिनांक 01.03.2021 की स्थिति के अनुसार, केंद्र सरकार अधीन सभी मंत्रालयों और विभागों में संस्वीकृत पदों की कुल संख्या 40,35,203 थी। रिक्तियों का होना और उन्हें भरा जाना, एक सतत प्रक्रिया है जो केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में पदों की स्थिति और आवश्यकता पर निर्भर करती है। भरी न गई रिक्तियों और की गई नियुक्तियों का ब्यौरा, संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा रखा जाता है। इसके अतिरिक्त, व्यय विभाग की वेतन अनुसंधान इकाई, वार्षिक रिपोर्टें प्रकाशित करती है जिनमें विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में संस्वीकृत पदों और पदस्थ कार्मिकों से संबंधित समेकित आंकड़े शामिल होते हैं। वेतन अनुसंधान इकाई की वार्षिक रिपोर्टें, व्यय विभाग की वेबसाइट: <https://doe.gov.in/hi/annual-report-pay-and-allowances> पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं।

सरकार ने रिक्त/भरे न गए पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से भरने के लिए समयबद्ध और अग्रिम कार्रवाई करने हेतु सभी मंत्रालयों/विभागों को अनुदेश जारी किए हैं। इन अनुदेशों के अनुसार, मंत्रालयों/विभागों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे सीधी भर्ती वाले पदों के संबंध में अपनी रिक्तियों की स्थिति की सूचना, संबंधित भर्ती एजेंसियों को देने के लिए अग्रिम कार्रवाई करें ताकि सीधी भर्ती की रिक्तियों को समयबद्ध तरीके से भरने में सहायता मिल सके। पदोन्नति के माध्यम से रिक्तियों को भरने के लिए, विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की बैठकें आयोजित करने हेतु एक मॉडल कैलेंडर निर्धारित किया गया है। सभी मंत्रालयों/विभागों से निर्धारित समय-सीमा का पालन करने का अनुरोध

किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पैनल समय पर तैयार हों और रिक्ति वर्ष के दौरान जब भी रिक्तियां उत्पन्न हो, उनका उपयोग किया जा सके। प्रतिनियुक्ति के माध्यम से रिक्त पदों को भरने के लिए मंत्रालयों/विभागों को वेतन मैट्रिक्स में स्तर 13क और उससे नीचे के पदों पर नियुक्ति करने की शक्ति प्रत्यायोजित की गई है। इन सभी उपायों से केन्द्र सरकार में नियुक्तियों की गति और मात्रा में तेजी लाने तथा रिक्त पदों को भरने में महत्वपूर्ण सहायता मिली है।

इसके अलावा, जून 2022 से, केंद्र सरकार में रिक्त पदों को संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा मिशन भर्ती के तहत मिशन-मोड में भरा जा रहा है। 45-50 शहरों में नियमित अंतराल पर रोजगार मेलों का आयोजन किया जा रहा है, जो केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों/संगठनों में रिक्त पदों को समयबद्ध तरीके से भरने के लिए उत्प्रेरक (कैटेलिस्ट) के रूप में कार्य करते हैं।
